जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 65 प्रभात जालोर, मंगलवार 11 जून, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

शपथ ग्रहण में मोदी अपने पुराने अवतार में प्रकट हुए

विभागों के वितरण में मोदी ना तो आर.एस.एस. के सम्मुख ना ही सहयोगी दलों के समक्ष झुके

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पार्टी के पास भले बहुमत से 32 सीटें कम हों, लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि "चलेगी तो मेरी ही।"

यह स्पष्ट है कि मोदी की कार्यशैली में बदलाव की उम्मीद नहीं है, चाहे मामला अधिक समायोजी होने का हो या सर्वसम्मति से सबको साथ लेकर चलने का। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद वहीं दस साल पुराने मोदी फिर से अपने रंग में आ गए हैं।

मोदी की भाजपा ने गृह, वित्त, रक्षा, विदेश और रेलवे आदि मंत्रालय रखे हैं। वे वैष्णव को पसंद करते हैं, इसलिए रेल के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी वैष्णव को दिए गए हैं।

शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है, जबकि स्वयं को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रुप में प्रोजैक्ट करने वाले धर्मेन्द्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय देकर उनका कद छोटा कर दिया गया है।

- यहां तक कि, अमित शाह को मंत्री नहीं बनाने व कम से कम गृह मंत्रालय नहीं देने के आर.एस.एस. के दबाव को भी पूरी तरह नकारा।
- आर.एस.एस. के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, मोदी के लिये अमित शाह की जरूरत अब दोगुनी हो गयी है।
- विपक्ष को अमित शाह व जांच एजेन्सियों के उपयोग से साधना है, साथ में अब सहयोगी दलों पर भी निगाह रखनी है।
- मोदी ने विपक्ष को न तो उतने कैबिनेट मंत्री दिये और न ही वे विभाग दिये, जिनकी विपक्ष को आशा थी।
- नायडू के खेमे से बने कैबिनेट मंत्री को नागरिक उड्डयन विभाग दिया तथा नीतीश के नुमाइंदे कैबिनेट मंत्री को मत्स्य विभाग सौंपा गया है।
- सहयोगी दल भी आमना-सामना करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि, इन सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ कई मुकदमे हैं।
- इण्डिया गठबंधन का, मगर कहना यह है कि, यह एक तरफा कहानी है, क्योंकि सहयोगी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के अजित पवार सरकार से बाहर हैं क्योंकि उनकी पार्टी को सिर्फ केन्द्रीय राज्यमंत्री का पद ऑफर किया गया था जिस उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जयन्त चौधरी भी केवल केन्द्रीय राज्यमंत्री हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एन.डी.ए. की किसी भी सहयोगी पार्टी के नेता स्वयं पर लगे केसों को देखते हुए मोदी को चुनौती देने की स्थिति में हैं? प्रत्यक्ष रुप से वे मोदी को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए प्र.मंत्री मोदी ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जून। प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि फंड जरी करने से संबंधित पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए।

मोदी ने कहा, "हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूर्णरूप से प्रतिबद्ध है। इसलिए यह बिल्कुल उचित है कि पदभार ग्रहण करने के बाद किसानों के कल्याण संबंधी प्रथम

- पहली फाइल में 9.3 करोड़ किसानों के हित में 20,000 करोड़ का फण्ड आवंटित किया गया है।

फाइल पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने आगे यह भी कहा कि आने वाले समय में हम किसानों के लिए व कृषि के क्षेत्र में और भी काम करते रहेंगे।

इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस फाइल में 9.3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए 20,00 करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री किसान निधि फंड्स की 17वीं किश्त जारी करने वाली फाइल पर प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर करने व उसका बड़ा दिखावा करने का मजाक बनाया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आंध्र की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पुरन्देश्वरी देवी लोकसभा अध्यक्ष होंगी?

पुरन्देश्वरी तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुई हैं। वे एन.टी. रामाराव की पुत्री हैं तथा राजनीतिक हल्कों में काफी लोकप्रिय हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जून। तेलुगू देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौता करते हुए, भाजपा नेतृत्व ने आंध्र प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष और स्वर्गीय एन.टी. रामाराव की बेटी दग्गूबाती पुरन्देश्वरी को लोकसभा स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा है।

तीसरी बार सांसद बनी पुरन्देश्वरी नरेन्द्र मोदी की दूसरी सरकार की सदस्य थीं। पुरन्देश्वरी एक लोकप्रिय राजनेता हैं, जिन्होंने हर बार अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीता है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में पुरन्देश्वरी राजमुन्दरी से जीती हैं। इसके पहले वो 2004 और 2009 में क्रमशः बापाटला और विशाखापटनम से सांसद चुनी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी बहनें हैं।

गठबंधन के दो प्रमुख पार्टनर टी.डी.पी. और जद (यू), दोनों को मोदी-3 मंत्रिमण्डल में 2-2 मंत्री पद मिले हैं- एक-एक कैबिनेट मंत्री और

- पुरन्देश्वरी देवी व चन्द्रबाबू नायडू की पत्नी बहनें हैं तथा पुरन्देश्वरी देवी ने भाजपा व तेलुगुदेशम पार्टी में तालमेल बिठाने में अहम् भूमिका निभायी थी, जिसके कारण आंध्र के विधानसभा चुनाव में एन.डी.ए. को भारी सफलता मिली और 175 सदस्यीय विधानसभा में अब एन.डी.ए. की 164 सीटें हैं।

एक-एक केन्द्रीय राज्य मंत्री। तथापि, कहा जा रहा है कि, दोनों पार्टियों- और विशेष रूप से टी.डी.पी. लोकसभा स्पीकर के पद के लिए अड़ी हुई है। दोनों पार्टियाँ भविष्य में अपनी पार्टी में होने वाली संभावित बगावत के प्रति सुरक्षा चाही हैं।

दल-बदल कानून के कारण, स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि, स्पीकर या चेयरमैन को, दल-बदल की सूरत में अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित मामलों में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है।

पुरन्देश्वरी ने टी.डी.पी. और जनसेना के साथ गठबंधन करने में भाजपा की मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप एन.डी.ए. को आंध्र प्रदेश में 175 विधासनभा सीटों में से 164 पर विजय हासिल करने में सफलता मिली। इस गठबंधन को 21 संसदीय सीटें भी मिलीं, 16 टी.डी.पी. से, तीन भाजपा और 2 जनसेना से।

मोदी के वर्तमान मंत्रिमण्डल की लिस्ट में पुरन्देश्वरी का नाम नहीं होने से इन चर्चाओं को बल मिला है कि, संभवतया उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाया जाएगा। जनसेना चीफ, पवन कल्याण का नाम भी लिस्ट में नहीं था। अटकले हैं कि वे 12 जून को शपथ लेने वाली चंद्रबाबू नायडू सरकार में बतौर मंत्री, संभवतया उपमुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले सकते हैं।

मोदी चन्द्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे 12 जून को

उसी दिन मोदी राजधानी, अमरावती के पुनर्निर्माण प्रोजैक्ट का शिलान्यास भी करेंगे

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जून। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती अब अपने पूरे रंग में आने वाली है और तेलुगूदेसम पार्टी (टी.डी.पी.) सुप्रीमो एन. चन्द्रबाबू नायडू की जीत के बाद तो वह अपनी पूर्ण भव्यता प्राप्त करेगी।

आंध्र प्रदेश का विभाजन कर बनाए गए नए राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनाए जाने के बाद नायडू ने नई राजधानी बनाने का कार्य शुरु किया था, लेकिन वर्ष 2019 में जगनमोहन रेड्डी के आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद नई राजधानी बनाने का काम स्थगित कर दिया गया था। जगनमोहन ने तीन राजधानियों की नीति पर चलना शुरु कर अमरावती का महत्व घटा दिया था।

नहीं के बराबर ध्यान दिए जाने के कारण आंध्र प्रदेश की अब तक कोई राजधानी नहीं है और टी.डी.पी. का आरोप है कि कई सरकारी भवन उजाड़ स्थिति में हैं तथा उनका जल्दी ही

- अमरावती के पुर्ननिर्माण की बात इसलिये उठी है, क्योंकि हालांकि चन्द्रबाबू नायडू ने आंध्र की नयी राजधानी अमरावती का निर्माण अपने मुख्यमंत्री काल में जोर-शोर से शुरू कराया था। परन्तु, उनके बाद नये मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अमरावती का महत्व कम करने की दृष्टि से नया सोच दिया था कि, आंध्र की एक नहीं तीन राजधानियां होंगी, बेहतर प्रशासन की दृष्टि से तथा नवनिर्मित प्रशासनिक सरकारी भवन पांच साल खाली पड़े रहे तथा रख रखाव के अभाव में खण्डहर का रूप लेने लगे थे।
- अब चन्द्रबाबू नायडू अमरावती के खण्डहर होते सरकारी भवनों का पुनः निर्माण करवाना चाहते हैं।
- चन्द्रबाबू नायडू भी आशा कर रहे हैं कि, राजधानी निर्माण के लिये मोदी कुछ विशेष पैकेज भी देंगे।
- चन्द्रबाबू नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी एन.डी.ए. के सदस्य थे तथा एन.डी.ए. की कोओर्डिनेटिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, वे अब दोबारा वह पद पाने के इच्छुक है।

कायाकल्प करने की जरुरत है। अब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर दस जुलाई को उपचुनाव

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जून। चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषित किया कि सात राज्यों में विधानसभा की 13 सीटों पर उपचुनाव 10 जुलाई को कराए जाएंगे और इन चुनावों की मतगणना जुलाई को होगी।

अधिकांश उपचुनाव विधायकों के त्याग पत्र दिए जाने व कुछ विधायकों

- चुनाव आयोग ने सोमवार को अपनी घोषणा में यह भी बताया कि, इन सीटों पर मतगणना 13 जुलाई को होगी।

की मृत्यु होने के कारण कराए जा रहे हैं।

वो प्रदेश, जहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं, वे बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब व हिमाचल प्रदेश हैं। सबसे अधिक चार सीटों पर उपचुनाव पश्चिम बंगाल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर और उत्तराखण्ड में दो सीटों पर।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चार बड़ी मिनिस्ट्रीज के मंत्रियों में कोई परिवर्तन नहीं

राजनाथ सिंह रक्षा, अमित शाह गृह, निर्मला सीतारमण वित्त व जयशंकर विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में चार प्रमुख विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई सरकार में भी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और एस. जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। वही नितिन गडकरी को भी उनके सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री के पद पर कायम रखा गया है उत्तराखंड के सांसद अजय टमटा दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा उनके राज्यमंत्री होंगे।

अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है और उन्हें अनुराग ठाकुर के स्थान पर सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार भी दिया गया है। अनुराग ठाकुर, जो हमीरपुर से भाजपा के सांसद हैं, को मंत्री नहीं बनाया गया है।

गुजरात के भाजपा सांसद सी.आर. पाटिल को जलशक्ति मंत्री बनाया गया है, भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलुगुदेशम के राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। मध्य प्रदेश की गुना सीट से जीते ज्योतिरादित्य से यह विभाग ले लिया गया है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को

- अश्विनी वैष्णव के प्रदर्शन से संतुष्ट प्र.मंत्री ने उन्हें भी पुनः रेलवे का चार्ज पुनः सौंपा तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंपी।
- नितिन गडकरी को भी सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय की पुरानी जिम्मेवारी पुनः सौंपी गयी है।

कृषि मंत्री बनाया गया है।

सहयोगी दल हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी को माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज विभाग दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पहली बार सांसद बने मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा तथा आवास एवं शहर विकास दिया गया है। श्रीपद यैसोनाईक को ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया है, वहीं तोखन साहू को आवास एवं शहर विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

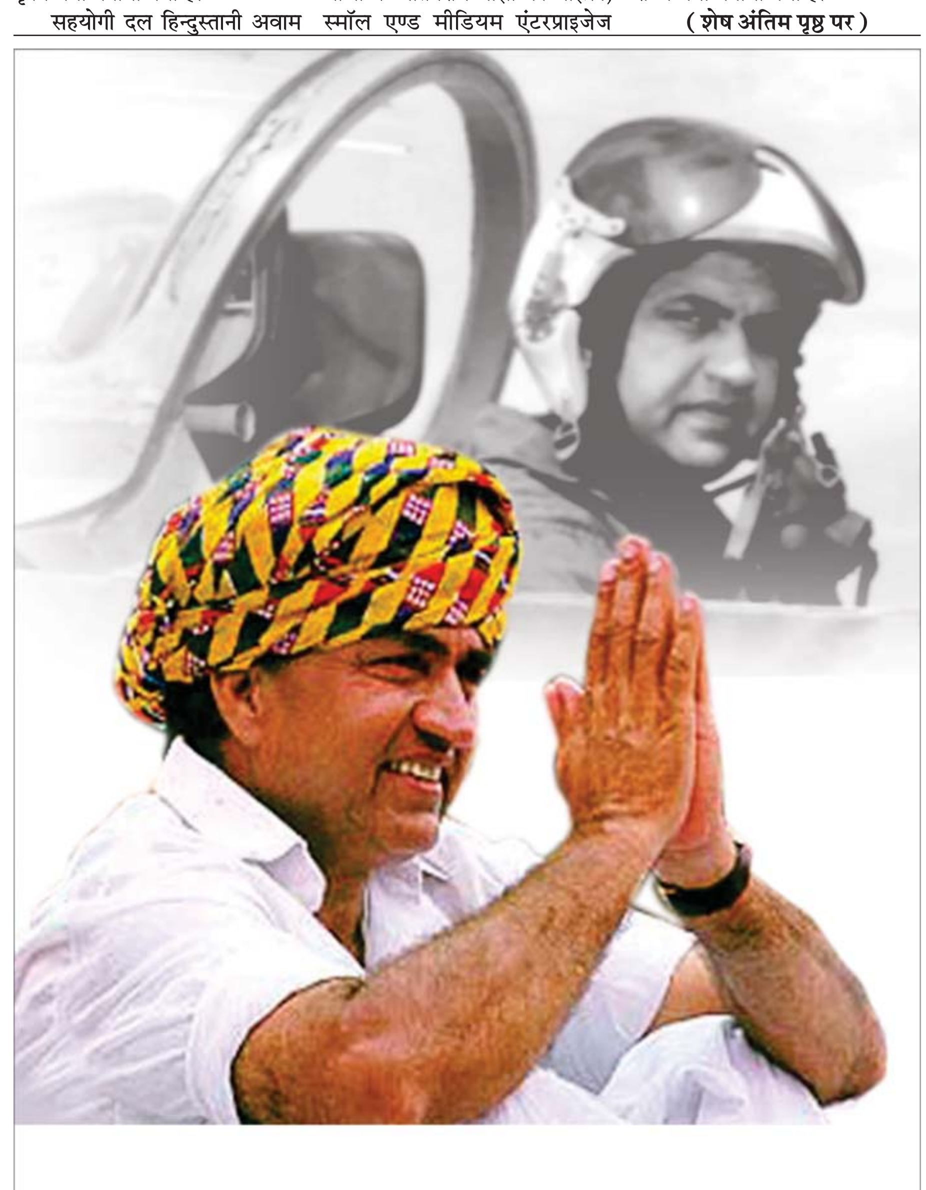

भावभीनी श्रद्धांजलि

स्व. श्री राजेश पायलट

10 फरवरी 1945 - 11 जून 2000

भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के चीफ अमित मालवीय पर "यौन शोषण" का आरोप

यह आरोप आर.एस.एस. के कार्यकर्ता व भाजपा नेता राहुल सिन्हा के रिश्तेदार शान्तनु सिन्हा ने अपने फेसबुक पेज पर लगाये

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जून। भारतीय जनता पार्टी की नैशनल इन्फॉर्मेशन एण्ड टैक्नॉलजी ने राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने आर.एस.एस. के सदस्य शांतनु सिन्हा से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है उनका आरोप है कि शांतनु ने फेसबुक पर उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक पोस्ट लिखी है।

भाजपा की आई.टी. सैल के प्रमुख अमित मालवीय ने आर.एस.एस. सदस्य शांतनु सिन्हा को फर्जी व अपमानजनक पोस्ट के लिए लीगल नोटिस भेजा है।

शांतनु सिन्हा, जो पश्चिम बंगाल के आर.एस.एस. कार्यकर्ता हैं, ने मालवीय पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मालवीय एक विवादास्पद नेता हैं, जिन पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी

- इन आरापों को कांग्रेस पार्टी ने पूरी हवा दी तथा कहा कि, उसका इस प्रकरण में इतना ही "इन्टरैस्ट" है कि, उन यौन शोषित महिलाओं को न्याय मिले, जिनका शोषण अमित मालवीय ने पांच सितारा होटलों में ही नहीं, वरन् भाजपा के कोलकत्ता ऑफिस में भी किया।
- कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि, अमित मालवीय को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिये, तभी प्रकरण की पूरी और निष्पक्ष जांच हो सकेगी, क्योंकि, मालवीय भाजपा में अति महत्वपूर्ण पद पर हैं।
- अमित मालवीय ने शांतनु सिन्हा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है।

बयानबाजी करने के आरोप लगते रहे हैं।

इसी बीच कांग्रेस ने यह मुद्दा लपक लिया है और मालवीय को उनके अधिकृत पद से हटाने की मांग की है।

एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया की शांतनु सिन्हा जो कि भाजपा नेता राहुल सिन्हा के भाई हैं, ने भाजपा आई.टी. सैल के मुखिया मालवीय पर "गलत कार्यों" से लिप्त होने का आरोप लगाया श्रीनेत ने कहा कि मालवीया न केवल 5 स्टार होटल्स में बल्कि प. बंगाल के भाजपा कार्यालयों में महिलाओं का यौन शोषण किया है।

उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाजपा महिलाओं के साथ न्याय करे। वास्तविकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के मात्र 24 घंटे में ही भाजपा के एक बड़े नेता, जो भाजपा की आई. टी. सैल का प्रमुख है, पर यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। हम मांग करते हैं कि, उन्हें उन पद से हटाया जाए जो कि महत्वपूर्ण पद हैं।

सुप्रिया ने कहा कि जब तक मालविया को पद से नहीं हटा दिया जाता तब तक महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो सकता है।

इन आरोपों के मद्देनजर मालवीय ने शांतनु

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)